

87

दिनांक:- 25-7-91

मुकदमा नम्बर :- 31/08
-:-:-:-:-



म या ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का मजदूत प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम चक्कीया वास तहसील जयपुर में अधाधिकृत भूमि की स्थिति का प्रकार बताया गई है :-

क्रम-सं.	मुकदमा नं.	खसरा नं.	रकबा बी-बि	छातेदारान/हितदारान का नाम
1.	31/88	160	16-11	दुर्गालाल, लल्लुराम, नृसिंगराम, प्रयोजीराम व लक्ष्मीनारायण पिता गोपाल पांडु आनंदा पिता जगन अहीर.

मुकदमा नं. 31/88 खसरा नं. 160

धारा-6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 160 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा
ग्राम वकपीथावास तहसील जयपुर में श्री दुर्गालाल, लल्लुराम, नृसिंगराम, प्रयोजीराम व लक्ष्मी
नारायण पिता गोपाल पांडु आनंदा पिता जगन अहीर के नाम दर्ज हैं।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत छातेदारान/हित
दारान को दिनांक 3-4-91 को नोटिस जारी किए गए तामील कुनिन्दा की हलफिया
रिपोर्ट के अनुसार छातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराया
गया तथा छातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 20-4-91 को
जारी किए गए। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार श्री शंकर यादव को नोटिस तामील कराया
गया जिसकी रशीद शामिल मिसल है। तत्पश्चात दिनांक 7-5-91 को दैनिक नवज्योती व
नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 व
10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

दिनांक 20-5-91 को अभिभाषक श्री मनदीप सिंह ने पांडु, आनंदा पुत्र जगन हि. 2/3
नृसिंगराम, लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल, महेश कुमार पुत्र श्री शिवनारायण, रामप्रसाद,
बंशीधर, श्रवण कुमार, राजेश पुत्रान दुर्गालाल हि. 1/3 का क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी
प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को वास्ते जवाब प्रति दी गई। श्री मनदीपसिंह
ने दस्तावेजों की सूची पेश की जिसमें नकल जमाबंदी, तत्पापित्त प्रतीतिपि, खसरा जमीन
की फोटो प्रति, नक्शा भवन फोटो प्रति, नकल रजिस्ट्री फोटो प्रति, नकल रजिस्ट्री फोटो
प्रति, नकल रजिस्ट्री फोटो प्रति, नकल रजिस्ट्री फोटो प्रति, नकल रजिस्ट्री फोटो प्रति,
उक्त सभी रजिस्ट्री फोटो प्रति को प्रमाणित की हुई है तथा 27-5-91 को लिखित
बहस भी प्रस्तुत की गई। क्लेम प्रार्थना पत्र में निम्न प्रकार से मुआवजे की मांग की गई है :-

भूमि अधिग्रहण अधिनियम
नगर विकास योजनाएं

जयपुर

भूमि खसरा नं. 160 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा जिसमें पांडु, आनंदा पुत्र जगन
हिस्सा 2/3 के वल भूमि के हिस्सेदार है। श्री लालत विजोर, नरसीराम लक्ष्मीनारायण महेश
कुमार पुत्रान दुर्गालाल का हिस्सा 1/3 बराबर भूमि स्ट्रेक्चर पेड़-पौधे, कुआं, आदि में
हिस्सेदार है जोकि प्रत्येक हितधारी अपनी हिस्से की भूमि व स्ट्रेक्चर आदि का मुआवजा
पाने का अधिकारी है। तथा ये भी निवेदन किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भूमि
के साथ वाल भूमि व उक्त भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु सन् 1988 में वैशाली नगर में
कम से कम 300 रुपये प्रति वर्ग गज दर निश्चित की गई है। जयपुरा के नियमानुसार उक्त
भूमि के आसपास की भूमि का आवासीय प्रयोजना हेतु काम पर लेने पर 40 रुपये प्रति वर्ग गज
विकास शुल्क लेना तय किया है साथ ही कुल भूमि का 60% भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है।

इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो कि न्यूनतम दर है :-

प्रति वर्ग गज न्यूनतम दर- 300/-रु. प्रतिवर्ग गज तथा विकास शुल्क कम करने पर 40 रुपये प्रति वर्ग गज । इस प्रकार प्रति बीघा 60 प्रतीकृत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज*260/- रुपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/-रुपये अर्थात् चार लाख इकहत्तर हजार नौ सौ मात्र प्रति बीघा बनती है । इस प्रकार प्रार्थी उक्त दर 4,71,900/-रुपये प्रति बीघा पाने का अधिकारी है ।

भूमि खसरा नं. 160 जिसका कुल क्षेत्रफल 50061 में से 40 प्रतीकृत 20024 कम करने पर शेष 30037 रहते हैं जिसकी बाजार दर 260/-रुपये वर्गगज के हिसाब से 78,09,620/- रुपये पाने का अधिकारी है ।

1-	जमीन का मुआयजा	78,09,620.00/-
2-	कुआं जिसकी गहराई 140 फुट चौड़ाई 9 फुट मोटर सादे सात हार्स पावर, स्टार्टर में स्वीच स्वें बिजली फिटिंग मय पाइप फिटिंग की राशि	7,03,00,000/-
3-	एक होद 9*4=36 स्क्वायर फिट दर 150/-रुपये	5,400/-
4-	भूमि को समतल कराने संबंधी उपयोग में लाने पर व्यय	50,000/-
5-	मकान जिसमें 7 कमरे । हाल । पशुगृह चाराघन एक व एक रस्ताई घर क्षेत्रफल 980। स्क्वायर फीट	15,68,160.00/-
6-	एक कमरा क्षेत्रफल 134.64 स्क्वायर फीट	21,542.00/-
7-	मिट्टी का डोला 9500 वर्ग गज दर 10 रु. प्रति वर्ग गज	95,000.00/-
8-	रेलिंग व लोन 18*40=720	72,000.00/-
9-	पूले 2000 प्रति वर्ष 5 रु. प्रति पूला	10,000.00/-
10-	सीमेन्ट की पाईप लाईन 1020 रेलिंग फीट	10,200.00/-
11-	होदी 9 जिसका क्षेत्रफल 6*4=24*9=216 वर्ग फीट	34,500.00/-
12-	नीम 7 पेड़ 30 वर्ष पुराने प्रति पेड़ 4000*7	28,000.00/-
13-	बम्बूल 53 पेड़ 25 वर्ष पुराने जिसमें कुम व पातडी व छडी प्रत्येक पेड़ से 200/-रु. आय व व्यय 40 रु प्रति छल पर 160*53*10	84,800.00/-
14-	छेजडी के 23 पेड़ 30 वर्ष पुराने की राशि	55,200.00/-
15-	रेड के 6 पेड़ 10 वर्ष पुराने की राशि	14,400.00/-
16-	रुई के 13 छल जिसकी कीमत 1000 रु प्रति पेड़	13,000.00/-
17-	रोजडी के 10 पेड़ 12 वर्ष पुराने दर 500 रु प्र. पेड़	5,000.00/-
	कुल योग:-	1,01,76,822.00/-



प्रति प्राप्त अधिकारी
भार विकास योजनाएं
जयपुर

प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया है कि केन्द्रीय भूमि अधिपत अधिनियम 1894 अर्थात् 1984 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 1980 से अर्वाइ की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि दी जाये। तथा केन्द्रीय भूमि अधिपत अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अधिपत वार्जेज पाने का अधिकारी है तथा अर्वाइ के पश्चात अर्थात् केन्द्रीय भूमि अधिपत अधिनियम की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत व्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने निवेदन किया है कि केन्द्रीय भूमि अधिपत अधिनियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर में भूमि की अधिपत के सम्बन्ध में राज्य सरकार को एवं भूमि अधिपत अधिकारी को निर्देशा दिये गये हैं कि जिस आतेदार की भूमि को अधिपत किया जाये उसको निवास भूखण्ड व व्यवसाय करने हेतु दुकान रिकर्व प्राइज पर आवंटन किया जाये। जैसा कि भूतपूर्व भूमि अधिपत अधिकारी नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर नगर विकास न्याय जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लाल कोठी योजना एवं मालवीय नगर योजना व संजय मार्केट जयपुर में जिन आतेदारों की भूमि को अधिपत किया गया है उन्हें एक हजार, पाँच सौ वर्ग गज से भूखण्ड और व्यवसाय करने हेतु दुकान दी गई है अतः प्रार्थी को भी निवास हेतु उक्त योजना में 1500 वर्ग गज का भूखण्ड व व्यवसाय करने हेतु एक दुकान रिकर्व प्राइज पर आवंटित की जाये।

प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 20 सितम्बर 1988 जो श्रीमती गायत्री देवी धर्मपत्नी श्री गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सांगानेर ने श्रीमती विमला देवी पत्नी नंदकुमार व श्रीमती कमला देवी पत्नी गोपाल लाल शर्मा जाति ब्राह्मण, व श्रीमती उषा देवी पत्नी मणीकान्त त्रिवेदी जाति ब्राह्मण व श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री कृष्ण। शर्मा व श्रवण कुमार पुत्र शिवदत्त त्रिवेदी जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं. 672 गणगौरी बाजार जयपुर जो विक्रय पत्र में प्रेतागण शब्द से सम्बोधित की गई है ग्राम मोलयावास अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नं. 460/584 रकबा 0.38 एकड़ पक्की स्थित है जिसे मुबालक रूपया 33000/- में बेचान दर्शाया गया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जाट की भूमि ग्राम ठीकौरवा अंतर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा नं. 206 रकबा 4 बीघा जिसका नया खसरा नं. 489 रकबा 0.97 हेक्टर पक्की है इस कृषि भूमि में हि. 1/4 की आतेदारी मुझ विजोला स्वयं के नाम है। दिनांक 7-9-89 को विक्रय पत्र द्वारा 90,000/- रूपये में बेचना बताया गया है।

श्री रामनारायण पुत्र भोरी लाल के विक्रय पत्र की फोटो प्रमाणित प्रति पेश की गई है भूमि ख.नं. 924 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व 924/1510 रकबा 19 बिस्वा 15... में कृषि भूमि मय कोठी पुकता, नाल जादि के हि. 1/4 प्रार्थी का है जो किता भी



भूमि अधिपत अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

जीवभाजित का विप्रेता अभिलिखित छातेदार प्रत्यक्ष रूप में बिना किसी अन्य व्यक्ति के व हिस्से के एक मात्र स्वामी हैं जिसे 85,000/-रु. प्रत्येक में दिनांक 1-2-91 को बेपान की प्रति पेश की गई है तथा एक और विक्रय पत्र की फोटो प्रति श्री प्रेम चंद गौलछा पुत्र उमराव गौलछा दिनांक 18-6-91 को पेश की तथा 22 सितम्बर, 1990 को विक्रय पत्र श्रीमती संगीता पत्नी विजय कुमार के विक्रय पत्र की फोटो प्रमाणित प्रति पेश की गई।

जीवप्रा के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने छातेदार ने जो मुआवजा राशि की मांग की है के संबंध में कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है लेकिन मौखिक रूप से कहा कि वह छातेदारान द्वारा जो क्लेम पेश किया गया है और उसके जो आपत्ति उठाई गई है वह आपत्तियाँ नियमानुसार धारा 4 के नोटिफिकेशन के बाद एवं धारा 5 स की आपत्तियों की सुनवाई की विधीय अवधि में प्रस्तुत करनी चाहिये थी। प्रार्थी द्वारा जो मुआवजे की मांग की गयी है वह बहुत अधिक है तथा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्टर आदि की जो मुआवजे की मांग की है वह बहुत अधिक है क्योंकि किसी भी रजिस्टर्ड वेल्यूयर से प्रमाणित नहीं कराया गया है एवं मनमाने तौर पर उक्त क्लेम को पेश किया गया है। छातेदार द्वारा जो भूमि के विक्रय पत्र पेश किए हैं वे किसी भी तरह से छातेदार के हक में नहीं है क्योंकि दिनांक: 27 सितम्बर, 1988 को विक्रय पत्र में भूमि की बेपान 33,000/-रु. बताया गया है। ये बेपान उक्त भूमि के एक छोटे से भाग का है और कृषि उपयोग के क्रय किया जाना प्रतीत नहीं होता है तथा अन्य रजिस्ट्रारों वर्ष 1988 के बाद की है जो मान्य नहीं है एवं भूमि का मुआवजे की राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है। छातेदारान द्वारा लिखित बहस जो पेश की गई है उसके क्रम में लेख है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम में यह स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अनिवार्य अवाप्ति में माना गया है तथा अन्य बिन्दु कानूनी है। हितदारान द्वारा जो आवास हेतु जो भूमि वादी गयी है वह दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। छातेदारान/हितदारान श्री योधी राम, दुर्गाताल को नोटिस तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध सूत्ररफा कार्यवाही अमल में लायी जावे तथा हितदारान द्वारा जो क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं और मुआवजा राशि की जो मांग की गयी है स्वीकार नहीं है इन्हें हितधारी व्यक्ति तो माना जा सकता है भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान भूमि के स्वामित्व संबंधी समस्त दस्तावेजात पेश करने पर ही दिया जावे। हम जीवप्रा अभिभाषक के कथन से सहमत हैं। हितदारान द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधी व राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत करने पर ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत

उपरोक्त मुकदमात में तार्वजिनिक नोटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित

e.1

—6

तहसील, संघायत समिति, नोटिफाईड बोर्ड, ग्राम संघायत व सरपंच को दिये गये
वस्था कराये गये जो दिनांक 29-4-91 को जारी किये गये ।

मुआवजा निर्धारण:-

जहाँ तक पुष्पराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न
है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक: 4-6/15/नविआ/87
दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य
सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता
में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पुष्पराज नगर योजना के 22 ग्रामों
में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस
सम्बन्ध में इस कार्य तब के पत्र क्रमांक: 353-355 दिनांक 11-2-91 के द्वारा
शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर तथा आयुक्त जीवप्रा
सर्व सचिव जीवप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा
गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जाये ।
इसके उपरान्त तत्काल-समय पर आयोजित निर्दिष्ट में भी मुआवजा निर्धारण
के लिए निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक
नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुष्पराज नगर योजना
के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी धारता को बुलाकर नेगोशिएशन
नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर
को निर्णय कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किया
है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के खण्ड
नोटिफिकेशन वर्ष 7-7-88 को हुआ था इसीलिए विभिन्न माननीय उच्च
न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप संजीयों
के यहाँ पुष्पराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमि की रीजल्यूशन की रकम दर
की उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त उत्तरा न्यायदान के धारतारान/हितधारान के
मुआवजे निर्धारण का प्रश्न है धारतारान द्वारा भूमि के मुआवजे की राशि



भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

तहसील, संपादित समिति, नोटिफिकेशन बोर्ड, ग्राम संचायक व सरपंच को दिये गये
वस्था कराये गये जो दिनांक 29.4.91 को जारी किये गये ।

मुआवजा निर्धारण:-

जहाँ तक पुष्पौराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न
है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक: 4-6/15/नविआ/87
दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य
सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता
में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पुष्पौराज नगर योजना के 22 ग्रामों
में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस
सम्बन्ध में इस कार्य त्रय के पत्र क्रमांक: 353-355 दिनांक 11.2.91 के द्वारा
शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर तथा जयपुर जिला
एवं सचिव जयपुरा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा
गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जाये ।
इसके उपरान्त तत्काल-समय पर आयोजित निविदाओं में भी मुआवजा निर्धारण
के लिए निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक
नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुष्पौराज नगर योजना
के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी धातेदार को बुलाकर नेगोशिएशन
नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा तत्काल समय पर
जो निर्णय कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किया
है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के खण्ड
नोटिफिकेशन वर्ष 7.7.88 को हुआ था इसीलिए विभिन्न माननीय उच्च
न्यायालयों के निर्णय के परिणाम में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप संजीवकों
के द्वारा पुष्पौराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रीजल्टेशन की वृद्धि दर
की उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त उत्तरा न्यायान के धातेदारान/रिजल्टरान के
मुआवजे निर्धारण का प्रश्न है धातेदारान द्वारा भूमि के मुआवजे की राशि



भूमि प्रकृति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

किता किती आधार के तथा मन्मानते तौर पर एवं ना ही किती रजिस्टर्ड
धरतपुत्र के स्टेशन को प्रमाणित कराया है अतः आवेदनपत्र को भूमि के
मुआवजे की राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से की जाती है तो
जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आवेदन नहीं है । हम जयपुर विकास
प्राधिकरण के अभिभावक के कम से सहमत है ।

लोक प्रार्थना न्याय के विधान के अनुसार इस सम्बन्ध में जीप्रा
विशेष तौर भूमि आवेदन की जा रही है जो भी जा आवेदन किया गया जीप्रा
के तद्विषय में प्रमाणिक:टी.डी.आर./91/336 दिनांक 8-8-91 द्वारा इस
सम्बन्ध में सुचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम
मोकुलपुरा तहसील जयपुर में 20,000/- रुपये प्रति बीघा के अनुसार भूमियों
का रजिस्ट्रेशन हुआ था । क्योंकि वहाँ तक इनके पत्र का सम्बन्ध है यह दर
उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उन मीजमक एवं तहसीलदार जयपुर के वहाँ से अपने
तार पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह बात हुआ कि धारा 4 के गजट
नोटिफिकेशन के समय भूमि का दर इससे अधिक नहीं था । तहसीलदार, जीप्रा
प्रथम ने अपने डू.ओ.नोट दिनांक 8-8-91 द्वारा ग्राम मोकुलपुरा तहसील
जयपुर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ज्ञान की विषय दर यही बताई है।

लोक इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी ज्ञान के आधार पर भी भूमि का
मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से जमाई जारी किये गये
ये ज्ञानका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जीप्रा के
अभिभावक ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन
किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से तब
की जाती है तो जीप्रा को कोई आवेदन नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व
भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आवेदन के ज्ञान में 24,000/- रुपये
प्रति बीघा की दर से जमाई जारी किये गये हैं ।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- रुपये
प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते
हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत जमाई जारी करने
के लिए 2 वर्ष की समयसीमा निवृत्त है ।



भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

जहाँ तक पेड़-पौधे, कुएँ, तालों एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकमीनी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश किये गये है ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर यदि कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है जिसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित तकमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा । मुआवजे का निर्धारण पॅरिशिफ्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है ।

केन्द्रीय भूमि अधिपत अधिनियम की धारा 23(1)-ए एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत तोलेषियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण पॅरिशिफ्ट "ए" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है ।

अतिरिक्त निदेशक प्रथम एवं तृतीय अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वी राज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अक्सर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन इन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अक्सर अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अधिपत अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है ।

अतः यह अवार्ड दिनांक: 25-7-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है ।

संदर्भ: पॅरिशिफ्ट "ए" गणना तालिका

भूमि अधिपत अधिनियम के अन्तर्गत

भूमि अधिपत अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी, नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक ए-6(15) दिनांक 31-7-91 के द्वारा अवार्ड अनुमोदित हो कर आज हुआ है। आज दिनांक 31-7-91 को अवार्ड सर इजलास में शामिल किया गया ।

भूमि अधिपत अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी, नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

परीशिष्ट "ए" गणना तालिका ग्राम:- चकपीथावास तहसील जयपुर ।

क्र.सं.	मुआं०	नाम छातेदार/हितदार	खण०	अवार्पितभूमि की भूमि का रकबा दर	मुआ०	भूमि का मुआ०	सोलेशियम 30%	अतिरिक्त 12%	कुल योग	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	31/88	दुर्गालाल, लखुराम, नृसिंहराम श्याजीराम, लक्ष्मीनारायण पि. गोपाल, पांचू, आनन्दा पि. जगन जाति अहीर सा. देह हितदारान रामप्रसाद, बंशीधर, श्रवण लाल, राजेश पुत्रान दुर्गालाल.	160	16 - 11	3, 97, 200/-	1, 45, 494/-	1, 19, 160/-		6, 61, 854/-	

- नोट:- 1. सोलेशियम 30% कॉलम संख्या : 6 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है ।
 2. अतिरिक्त राशि 12% की गणना धारा 481 के गजट नोटिफिक 7.7.1988 से 21.7.91 तक
 3. हितदारान-राम प्रसाद, बंशीधर, श्रवणलाल, राजेश कुमार, पुत्रान, दुर्गालाल को, उत्तराधिकारी का प्रमाण-पत्र व राजस्व सम्बन्धी, देस्ताव जात प्रस्तुत करने पर ही अवाइड में से उनके हिस्से की राशि देय होगी ।

भूमि अवार्पित अधिकारी,
 नगर विकास योजनाएं,
 जयपुर ।